

closure of phone whichever is earlier. This deposit amount carries no interest. Crores of rupees will be collected this way and used by Government for years without any interest.

The charges of local calls, trunk calls and other deposits have been considerably increased. Moreover, the Department is unable to give satisfactory service to customers. Many a times, telephone connections are cut for not having paid the arrears. To add to all this, the Department is now informing the customers to pay security deposits towards arrears, in order to improve the paying habit of the customers. Such notices are also issued to those who are regularly paying the arrears. This is most insulting and annoying.

In Chiplun town in Ratnagiri district in Maharashtra such notices are issued to more than 50% of the phone subscribers.

I, therefore, request and urge upon the Minister of Communications to reconsider the matter and direct the authorities concerned to withdraw the orders and stop collecting security deposits towards arrears and not to harass telephone subscribers.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Before I bring my urgent matter for your consideration, I would like to bring to your notice that on all these matters of urgent nature which the Members of Parliament have brought to the notice of the Government, the action taken by the Government is very very late.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I am supporting his view. Rule 377 has become a mockery.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बिल्कुल सही कह रहे हैं।

SHRI RAJESH PILOT: When we cannot bring it under any other Rule, we bring the matter under Rule 377. I want to bring something for your consideration.

MR. CHAIRMAN : You kindly read out the statement

(Interruptions)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत महत्व की बात है। आवास मंत्री सामने बैठे हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनको निदेश दिया जाए कि यह हर बात का जवाब दिलवायें। मैंने अब तक 14, 15 नोटिस दिए हैं और अभी तक एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई।

MR. CHAIRMAN: Is this an occasion to mention all this ?

(vii) NEED TO MONITOR THE PROGRESS OF RESERVATION OF SERVICE QUOTA FIXED FOR EX-SERVICEMEN

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur) : Sir, I would like to bring the following matter under Rule 377:

It has been stated time and again that concession in the form of reservation in Central Government and State Government services, the percentage of reservation fixed for ex-servicemen has not been fully materialised although as per the Government policy, the public sector is also supposed to have reserve quota for Ex-servicemen. After touring most of the States and meeting the Ex-servicemen all over the country I wish to bring to the notice of the concerned State authorities through the Central Government that monitoring of this procedure needs to be done immediately and also smoothen the system in all parts of the country by nominating President of District Soldier Board. All State Governments may please be requested to call for figures

[Shri Rajesh Pilot]

from each district, of unsettled Ex-servicemen and the same may please be transmitted to the Centre for information to the nation for better cause of those people who sacrificed their yesterday for our today.

(viii) NEED TO IMPROVE THE RAIL SERVICES ON NORTH-EASTERN RAILWAY.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): सभापति महोदय मैं आप के माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे की ओर ले जाना चाहता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे देश के पूर्व और उत्तर यानी वाराणसी, लखनऊ गोरखपुर, बलिया से लेकर गोहाटी, आसाम तक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की करोड़ों जनसंख्या के लिए यह एक मात्र यात्रा का साधन है।

किसी गाड़ी का समय पर आना एक दम ऐतिहासिक बात है। एक घंटे से लेकर आठ-आठ घंटे तक लेट चलना इस रूट की रेलगाड़ी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी है। आप दो चार मील जाइए, जहरी काम कर के लोट आइये गाड़ी खड़ी की खड़ी मिलेगी। वाराणसी छपरा शाखा की एक गाड़ी वर्षों से सदा पांच से आठ घंटे लेट चलती है। इन्दारा दोहरी घाट, इन्दारा बलिया शाखा की गाड़ियां जब स्टेशन पर पहुंच जायें तभी समय है, सरकारी समय सारिणी की कोई आवश्यकता नहीं।

डब्बों की दशा का कोई ठिकाना नहीं। मूंगफली के छिलके पूरे डब्बे में विराजमान हैं। टायलेट में घुसते ही जलती हो जाएगी। सफाई ठीक से नहीं

होती। बल्व और पंखा इन गाड़ियों में काम नहीं करते। पानी महीने में एक दिन शायद भरा जाता हो। ये बातें अतिशयोक्ति प्रायः हर व्यक्ति के लिए लगेंगी किन्तु उस क्षेत्र के निवासी या रेल यात्री को लगेगा जैसे बहुत कम ही कहा गया है।

मान्यवर, बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है कि वाराणसी भटनी के बीच छोटी रेल लाइन हटा कर बड़ी लाइन होगी। पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने काम द्रुत गति से चलवाया। एक आशा बंधी लेकिन फिर काम ढीला हो गया।

मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान ले जायें। शीघ्र इस क्षेत्र की जनता पर मेहरबानी कर यहां की रेलों में सुधार करवायें ताकि रेलों के प्रति इधर के लोगों में विश्वास पैदा हो।

(ix) NEED FOR TAKING OVER OF VINOD AND VIMAL TEXTILE MILLS OF UJJAIN

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ:

देश के कपड़ा उद्योग की स्थिति दिन-दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छे प्रबन्ध के अभाव में एक के बाद एक मिल घाटे में जा रही है और इन मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का भविष्य अन्धकार में है। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन और मजदूरी, उनको दी जाने वाली सुविधाएं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम